



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

65-2015/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 15, 2015 (CHAITRA 25, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/488.—ग्राम पंचायत भाडावास के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/609 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला रेवाड़ी की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	रेवाड़ी	भाडावास	14	5	6	2	1	4
2	रेवाड़ी	खरसानकी	6	2	0	0	1	3
3	रेवाड़ी	अकबरपुर	6	2	0	0	1	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/489.—ग्राम पंचायत रंगाला के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6 जनवरी, 2015 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2015/621 दिनांक 6 जनवरी, 2015 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला मेवात की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	तावडू	रंगाला	9	3	2	1	0	5
2	तावडू	खोरी कलां	18	6	2	1	0	11
3	तावडू	खोरी खुर्द	6	2	2	1	0	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/490.—ग्राम पंचायत फरीदपुर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/610 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला फरीदाबाद की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	फरीदाबाद	फरीदपुर	12	4	3	1	1	5
2	फरीदाबाद	सदपुरा	9	3	2	1	1	4

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/491.—ग्राम पंचायत खटावली के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/609 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला रेवाड़ी की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	रेवाड़ी	खटावली	8	3	4	2	1	2
2	रेवाड़ी	राजपुरा आलमगिरपुर	8	3	4	2	1	2

नवराज सन्धु ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/492.—ग्राम पंचायत ब्रास के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/611 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला करनाल की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	निसिंग स्थित चिड़ाओं	ब्रास	16	6	5	1	1	6
2	निसिंग स्थित चिड़ाओं	ब्रास खुर्द	11	4	1	1	1	6

नवराज सन्धु ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/493.—ग्राम पंचायत बेगा के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/616 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला सोनीपत की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	गन्नौर	बेगा	16	6	4	2	1	7
2	गन्नौर	पीरगढ़ी	8	3	0	0	1	4

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/494.—ग्राम पंचायत जैनपुर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/618 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला महेन्द्रगढ़ की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	नांगल चौधरी	जैनपुर	7	3	0	0	1	3
2	नांगल चौधरी	बिहारीपुर	7	3	1	1	1	3
3	नांगल चौधरी	मौसमपुर	7	3	2	1	1	2

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/495.—ग्राम पंचायत गौधोला के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 जनवरी, 2015 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2015/621 दिनांक 8 जनवरी, 2015 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला मेवात की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	पुन्हाना	गौधोला	14	5	1	1	1	8
2	पुन्हाना	टुण्डलाका	8	3	0	0	1	4

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/496.—ग्राम पंचायत गढी सिकन्दरपुर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 मार्च, 2015 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2015/626 दिनांक 2 मार्च, 2015 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला पानीपत की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	पानीपत	गढी सिकन्दरपुर	20	7	2	1	1	11
2	पानीपत	रामनगर	8	3	0	0	1	4

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/497.—ग्राम पंचायत कलिंगर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 जनवरी, 2015 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2015/621 दिनांक 8 जनवरी, 2015 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला मेवात की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	नूँह	कलिंगर	13	5	0	0	1	7
2	नूँह	बीबीपुर	9	3	0	0	1	5

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/498.—ग्राम पंचायत बिलासपुर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/613 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला गुडगांव की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	पटौदी	बिलासपुर	12	4	1	1	1	7
2	पटौदी	बिलासपुर कलां	7	3	2	1	0	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/499.—ग्राम पंचायत शादीपुर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/609 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला रेवाड़ी की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	जाटूसना	शादीपुर	7	3	3	1	1	1
2	जाटूसना	राजावास	7	3	1	1	1	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/500.—ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर बसई के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/609 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला रेवाड़ी की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	बावल	मुकुन्दपुर बसई	7	3	3	1	0	2
2	बावल	खेड़ी मोतला	6	2	0	0	1	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/501.—ग्राम पंचायत खेडी गुजरान के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/610 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला फरीदाबाद की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	फरीदाबाद	खेडी गुजरान	7	3	1	1	1	3
2	फरीदाबाद	पाखल	8	3	1	1	1	4

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/502.—ग्राम पंचायत खेड़ा खुर्रमपुर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/613 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला गुडगांव की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	फारुखनगर	खेड़ा खुर्रमपुर	15	5	2	1	1	8
2	फारुखनगर	खुर्रमपुर	9	3	1	1	1	5

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/503.—ग्राम पंचायत शेखपुर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/609 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला रेवाड़ी की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	बावल	शेखपुर	7	3	3	1	1	1
2	बावल	दुल्हेडा कलां	6	2	4	2	0	0

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/504.—ग्राम पंचायत लुहिगाकलां के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 जनवरी, 2015 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2015/621 दिनांक 8 जनवरी, 2015 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला मेवात की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	पुन्हाना	लुहिगा कलां	16	6	0	0	1	9
2	पुन्हाना	पिपरौली	12	4	0	0	1	7

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/505.—ग्राम पंचायत गहली के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/618 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला महेन्द्रगढ़ की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	नारनौल	गहली	11	4	2	1	1	5
2	नारनौल	मकसूसपुर	6	2	1	1	0	4

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/506.—ग्राम पंचायत कानौली के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/612 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला पलवल की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	हथीन	कानौली	7	3	2	1	0	3
2	हथीन	खेडली जीता	7	3	1	1	1	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/507.—ग्राम पंचायत झुण्डपुर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/616 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला सोनीपत की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	मुरथल	झुण्डपुर	10	4	4	2	1	3
2	मुरथल	टाण्डा	8	3	7	3	1	0
3	मुरथल	जगदीशपुर	10	4	5	2	1	2

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/508.—ग्राम पंचायत भौडाकलां के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/613 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला गुडगांव की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	पटौदी	भौडाकलां	20	7	5	2	1	9
2	पटौदी	ढाणी कुम्भावास	9	3	1	1	1	5
3	पटौदी	ढाणी शंकरवाली	8	3	1	1	1	4
4	पटौदी	ढाणी चित्रसेन	7	3	0	0	0	4

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/509.—ग्राम पंचायत छप्परा जागीर के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/611 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला करनाल की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	करनाल	छप्परा जागीर	6	2	2	1	1	2
2	करनाल	छप्परा खेड़ा	8	3	1	1	1	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/510.—ग्राम पंचायत नागल के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/611 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला करनाल की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	इन्द्री	नागल	7	3	5	2	1	0
2	इन्द्री	ढाणी कमालपुर गडरियान	6	2	0	0	1	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/511.—ग्राम पंचायत रीडका के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/612 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला पलवल की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	हथीन	रीडका	8	3	2	1	1	3
2	हथीन	गढी विनोदा	6	2	1	1	1	3

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 32/17/2013-4आई0बी0-1.— चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 32/17/2013-4आई0बी0-1, दिनांक 24, दिसम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा गांव रायलीयावास, निगानीयावास, तहसील बावल तथा गांव निखरी, पिथनवास, लोधाना, खिजूरी, कसौला, माजरी डोढा, पांचौर, बूढला, लाधुवास, सालावास तथा पिवारा, तहसील तथा जिला रेवाड़ी में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सम्बन्धित उपयोगों जोकि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के अंतर्गत एक अरली बर्ड परियोजना के विकास के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)—एवं—भूमि अर्जन कलक्टर, रिवाड़ी को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT
ORDER

The 15th April, 2015

No. 32/17/2013-4IB-I.—Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 32/17/2013-4IB-I, dated the 24th December, 2014 issued notification under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public

expense, for a public purpose, namely, for development of a Mass Rapid Transport System and allied uses, an early bird project under the Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project, in villages Raliyawas, Niganiawas, tahsil Bawal and villages Nikhri, Pithanwas, Lodhana, Khijuri, Kashola, Majri Duda, Panchor, Bhudla, Ladhuwas, Salawas and Piwara, tahsil and district Rewari by Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the Sub Divisional Officer (Civil)-cum-Land Acquisition Collector, Rewari to take order of the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,

Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
आदेश
दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 2/19/2013-1आई0बी0-1।- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 2/19/2013-1आई0बी0-1।, दिनांक 1 सितम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि के छोटे हुए टुकड़े, सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव कुताना, तहसील तथा जिला रोहतक में, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 60 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण करने तथा औद्योगिक सम्पदा में अन्य सेवाओं के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, रोहतक को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT
ORDER

The 15th April, 2015

No. 2/19/2013-1IB-II.-Whereas, the left out pockets of land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 2/19/2013-1IB-II, dated the 1st September, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), read with clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, has been declared to be needed by the Government, for a public purpose, namely, for construction of 60 meters wide road and other services in Industrial Estate in village Kutana, tehsil and district Rohtak by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Rohtak to take order of the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,

Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
आदेश
दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 32/9/2013-4आई0बी0-I- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 32/9/2013-4आई0बी0-I, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव भांगरौला, बास कुशला तथा कांकरौला, तहसील तथा जिला गुडगांव में गुडगांव-मानेसर शहरी कॉम्प्लेक्स- 2031 ए डी विकास प्लान के अनुसार उत्तरी परिधि सड़क से आदर्श औद्योगिक नगर मानेसर को जोड़ने के लिए सैक्टर एम 14 तथा एम 15 और एम 6 तथा एम 15 के बीच सैक्टर सड़क निर्माण के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, गुडगांव को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT
ORDER

The 15th April, 2015

No. 32/9/2013-4IB-I.-Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 32/9/2013-4IB-I, dated the 17th December, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for construction of Sector Road between Sector M14 and M15 and M6 and M15 for connecting Industrial Model Township Manesar with Northern Periphery road as per Gurgaon-Manesar Urban Complex- 2031 AD Development Plan in villages Bhangrola, Bas Kushla and Kankrola, tehsil and district Gurgaon;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon to take order of the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
आदेश
दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 32/15/2013-4आई0बी0-I- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 32/15/2013-4आई0बी0-I, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात् हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना तथा विकास निगम लिमिटेड द्वारा गांव फाजिलवास, बिनौला, बिलासपुर, राठीवास तथा सिद्धरावली, तहसील मानेसर, जिला गुडगांव में मेट्रो रेल ट्रेक तथा सहबद्ध उपयोग स्थापना के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, गुडगांव को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT
ORDER

The 15th April, 2015

No. 32/15/2013-4IB-I.—Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 32/15/2013-4IB-I, dated the 17th December, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for setting up Metro Rail Track and allied uses in villages Fazilwas, Binola, Bilaspur, Rathiwas and Sidhrawali, tahsil Manesar, district Gurgaon, by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon to take order of the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
आदेश
दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 2/13/2013-1आई0बी0.।।- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 2/13/2013-1आई0बी0.।।, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् कस्बा करनाल, सैक्टर-3, तहसील तथा जिला करनाल, में सैक्टर सड़कों के निर्माण के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी—एवं—भूमि अर्जन कलक्टर, करनाल को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT
ORDER

The 15th April, 2015

No. 2/13/2013-1IB-II.—Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 2/13/2013-1IB-II, dated the 17th December, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for construction of sector roads in Sector-3 at Karnal, Kasba Karnal, tehsil and district Karnal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Karnal to take order for the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
आदेश
दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 2/14/2013-1आई0बी0.।।- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 2/14/2013-1आई0बी0.।।, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् कस्बा करनाल के सैक्टर-37 तथा गाँव कम्बोपुरा, तहसील तथा जिला करनाल, में औद्योगिक सम्पदा के विकास के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, करनाल को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT
ORDER

The 15th April, 2015

No. 2/14/2013-1IB-II.-Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 2/14/2013-1IB-II, dated the 18th December, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for development of Industrial Estate in Sector 37 of Kasba Karnal and village Kambopura, tehsil and district Karnal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Karnal to take order for the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
आदेश
दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 32/13/2013-4आई0बी0-।।- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 32/13/2013-4आई0बी0-।।, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा औद्योगिक सैक्टर-34 तथा 35, में सड़कों के निर्माण और चौड़ा करने हेतु गांव नरसिंहपुर, बेगमपुर खटोला तथा खाण्डसा, तहसील तथा जिला गुडगांव के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, गुडगांव को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

ORDER

The 15th April, 2015

No. 32/13/2013-4IB-I.—Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 32/13/2013-4IB-I, dated the 23rd December, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, for a public purpose, namely, for construction and widening of roads in Industrial Sectors 34-35 in villages Narsinghpur, Begampur Khatola and Khandsa, tahsil and district Gurgaon, by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon to take order of the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
आदेश
दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 32/11/2013-4आई0बी0-I.— चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 32/11/2013-4आई0बी0-I, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव लखनौला, नहारपुर कासन, मानेसर, नौरंगपुर तहसील मानेसर तथा गांव कांकरौला तहसील तथा जिला गुडगांव में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, फेज-V, की अर्जित भूमि के समेकित योजना तथा विकास के लिए वाणिज्यिक, आवासीय, संस्थागत, मनोरंजनात्मक तथा अन्य लोक उपयोगिता हेतु प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, गुडगांव को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

ORDER

The 15th April, 2015

No. 32/11/2013-4IB-I.—Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 32/11/2013-4IB-I, dated the 23rd December, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for integrated planning and development of the acquired land of Phase-V, Industrial Model Township Manesar to be used for Industrial, Residential, Commercial, Institutional, Recreational and other Public Utilities in villages Lakhnoula, Naharpur Kasan, Manesar, Naurangpur, tahsil Manesar and village Kankrola, tahsil and district Gurgaon, by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon to take order of the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,

Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 2/15/2013-1आई0बी0-।।- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 2/15/2013-1आई0बी0-।।, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, रोज-का-मेव, मेवात के एकीकृत और योजनाबद्ध विकास हेतु गांव बहादूरी, रेवासन, खेड़ली-कंकर, रूपाहेड़ी, रोज-का-मेव तथा महरौला, तहसील नूह, जिला मेवात में औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, मनोरंजनात्मक और अन्य लोक उपयोगिताओं के समेकित शहरी कम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने हेतु अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, मेवात, नूह को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

ORDER

The 15th April, 2015

No. 2/15/2013-1IB-II.-Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 2/15/2013-1IB-II, dated the 23rd December, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for integrated and planned development of Industrial Model Township at Roz-Ka-Meo, Mewat, to be developed as Integrated Urban Complex having Industrial, Commercial, Institutional, Recreational and other Public Utilities in villages Bahaduri, Rewason, Khedli-Kankar, Roopaheri, Roz-Ka-Meo, Mehrola, tahsil Nuh, district Mewat, by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Mewat, Nuh to take order for the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,

Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
आदेश
दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या 2/9/2013-1आई0 बी0- II .- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 2/9/2013-1आई0 बी0- II, दिनांक 29 अगस्त, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव लहेड़ी तथा गढ़ी केसरी, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत में औद्योगिक सम्पदा फेस-III के निर्माण के लिए अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, सोनीपत को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT
ORDER

The 15th April, 2015

No. 2/9/2013-1IB-II.- Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 2/9/2013-1IB-II, dated the 29th August, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894) read with clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for the development of Industrial Estate, Phase-III, in villages Lalheri and Garhi Kesari, tahsil Ganaur, district Sonipat;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Sonipat to take order of the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.